



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264465
CG-DL-E-08072025-264465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2969]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 2025/आषाढ़ 17, 1947

No. 2969]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 2025/ASHADHA 17, 1947

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

का.आ. 3036(अ).—पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में से सन्निधि, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, साथ ही यह किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने के लिए दस्तावेजों की बहुलता की आवश्यकता को कम करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देता है;

और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथास्थिति उक्त मंत्रालय या उक्त विभाग कहा गया है), दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम (सिपडा) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के अधीन दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का संचालन कर रहा है;

और इस स्कीम के तहत, नकद लाभ अर्थात् परिवहन लागत, भोजन और आवास लागत, वाहन लागत, पोस्ट प्लेसमेंट समर्थन के लिए लागत आदि जो भी इस स्कीम के मानदंडों के अनुसार लागू हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त लाभ कहा गया है), उक्त स्कीम और उसके संबंध में जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्देशों के अधीन बताए गए अनुसार दिव्यांगजनों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् लाभार्थी कहा गया है) को दिया जाता है;

और उक्त स्कीम के लिए व्यय भारत की संचित निधि से किया जाता है;

और उक्त विभाग यह चाहता है कि उक्त सरकार उक्त लाभ की प्राप्ति के लिए एक शर्त के रूप में लाभार्थी की पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से, यह अपेक्षा करती है कि ऐसे लाभार्थी का प्रमाणीकरण करना होगा, या उस आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करना होगा या यदि किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उससे आधार नामांकन के लिए आवेदन कराना होगा;

अतः अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, भारत सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. (1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह अपना अधिप्रमाणन कराए, या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे।

(2) यदि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है, तो उससे यह अपेक्षित होगा कि वह नामांकन के लिए आवेदन करे;

परंतु यदि वह व्यक्ति एक बच्चा है, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक की सहमति से किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, मंत्रालय या विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित करना होगा, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है, या उपयुक्त उपायों के माध्यम से उनका आधार विवरण अद्यतन करना सुनिश्चित करना होगा, जिसमें रजिस्ट्रारों के समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन केंद्रों की स्थापना करना या स्वयं रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन प्रदान करना सम्मिलित है:

परन्तु ऐसे लाभार्थी को आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, वह निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके, जिसके लिए वह हकदार है और जो प्रस्तुति के समय वैध हैं, या यदि उक्त पहचान के लिए उक्त विभाग द्वारा प्रदान किया गया या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर पहचान हेतु विवरण देने के लिए उसकी तैयारी या रखरखाव का कार्य देखने वाले प्राधिकारियों के डाटाबेस से ऐसे दस्तावेजों की विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने में सहायता करता है, परंतु इस तरह सूचना देने हेतु लाभार्थी को अपनी सहमति देनी होगी, अर्थात्:—

(क) 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे के लिए जिसे आधार संख्या नहीं दिया गया है:

(क) नामांकन केंद्र पर नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने पर लाभार्थी को ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) अंतर्विष्ट है; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक यह प्रमाणित करने के लिए कि लाभार्थी 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, अर्थात्:—

(i) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्री अधिनियम, 1969 के अधीन दिया गया जन्म प्रमाण पत्र, जिसे लाभार्थी के जन्म से संबंधित जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से लिया गया है;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) स्कूली शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10 वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12 वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण पत्र या विवरणी;

(iv) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधि से विरोधरत बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के साथ रजिस्ट्री बाल देखभाल संस्थान में रखा गया है, तो ऐसे संस्थान के प्रभारी अधिकारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र, अथवा

(v) एक विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(i) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो उसका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड;

(ii) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो एक विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण पत्र;

- (iii) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
- (iv) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या वैधता समाप्त हुए विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत में रहने के संबंध में दीर्घकालिक वीजा ; अथवा
- (ग) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी की तस्वीर हो, ताकि माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध साबित हो सके, अर्थात्:—
- i. राशन कार्ड;
 - ii. राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी है, जिसका पद तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं है;
 - iii. सरकारी इकाई या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा किसी सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
 - iv. भारतीय पासपोर्ट;
 - v. स्कूली शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10 वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12 वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण पत्र या विवरणी;
 - vi. देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधि से संघर्षरत बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के साथ रजिस्ट्री बाल देखरेख संस्थान में रखा गया है, तो ऐसे संस्थान के प्रभारी अधिकारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र, अथवा
 - vii. एक विदेशी नागरिक के संबंध में,—
 - (I) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो उसका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड;
 - (II) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो एक विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण पत्र;
 - (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
 - (IV) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या वैधता समाप्त हुए विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत में रहने के संबंध में दीर्घकालिक वीजा ; अथवा
 - viii. एक लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक संरक्षक है और विधिक संरक्षकता साबित करने हेतु दत्तक ग्रहण आदेश (अडोप्शन ऑर्डर) या अन्य दस्तावेज है, जिसे न्यायालय या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिषक घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियम और विनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; अथवा
 - ix. कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि उक्त **विभाग विनिर्दिष्ट** करे।
- (ख) 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए, जिन्हें आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है:
- (क) नामांकन केंद्र पर नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने पर लाभार्थी को ऑपरेटर द्वारा प्रदान की गई पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) अंतर्विष्ट है; और
 - (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, जिसमें लाभार्थी का फोटो हो, अर्थात् : —

- (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र;
- (ii) राशन कार्ड;
- (iii) एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र या अधिवास प्रमाण पत्र, जो एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का राजस्व अधिकारी है, जिसका पद तहसीलदार के पद से नीचे का नहीं है;
- (iv) किसी सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा सेवानिवृत्त या कार्यरत लोक सेवक या उसके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;
- (v) भारतीय पासपोर्ट;
- (vi) स्कूली शिक्षा के किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10 वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12 वीं कक्षा के अंकों का प्रमाण पत्र या विवरणी;
- (vii) किसी सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;
- (viii) दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, या दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी) कार्ड;
- (ix) भारत में जारी किये गए ड्राइविंग लाइसेंस;
- (x) देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे या विधि से संघर्षरत बच्चे के संबंध में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन संबंधित राज्य सरकार के साथ रजिस्ट्री बाल देखभाल संस्थान में रखा गया है, तो ऐसे संस्थान के प्रभारी अधिकारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी उसकी जन्म तिथि विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र, अथवा
- (xi) एक विदेशी नागरिक के संबंध में,—
 - (I) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक है, तो उसका ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड;
 - (II) यदि वह एक तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्री प्रमाण पत्र;
 - (III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;
 - (IV) यदि वह ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्डधारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति है, तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या वर्तमान में वैध या वैधता समाप्त हुए विदेशी पासपोर्ट के साथ भारत में रहने के संबंध में दीर्घकालिक वीजा ; अथवा
- (xii) एक लाभार्थी के संबंध में जिसके पास विधिक संरक्षक है और विधिक संरक्षकता साबित करने हेतु दत्तक ग्रहण आदेश (अडोप्शन ऑर्डर) या अन्य दस्तावेज है, जिसे न्यायालय या संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिषक घात, मानसिक मंदता और बहुनिःशक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और उक्त अधिनियमों के अधीन बनाए गए लागू नियम और विनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो; अथवा
- (xiii) कोई अन्य दस्तावेज जैसा कि उक्त **विभाग विनिर्दिष्ट** करे।

(4) उक्त **विभाग** द्वारा अभिहित अधिकारी जो उनकी ओर से खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उनकी विषय-वस्तु को प्रमाणित करने वाली सूचना के संबंध में निम्नलिखित जांच करेगा,—

- (क) माई आधार पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर इलेक्ट्रॉनिक पहचान (ईआईडी) जमा करके नामांकन अनुरोध की स्थिति की जांच करना ताकि यह पुष्टि हो सके कि इलेक्ट्रॉनिक पहचान (ईआईडी) वैध है और नामांकन अनुरोध अस्वीकार नहीं किया गया है; तथा

(ख) अन्य दस्तावेजों की जांच करना और इस प्रयोजन हेतु, वह ऐसे दस्तावेजों में निहित सूचना की तैयारी या रखरखाव से संबंधित किसी सरकारी इकाई या प्राधिकरण की सहायता ले सकेगा तथा उसके साथ प्रस्तुत सूचना साझा कर सकेगा।

2. लाभार्थियों को उक्त लाभ आसानी से प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए, मंत्रालय उक्त स्कीम के अंतर्गत आधार संख्या की अपेक्षा के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

3. जहां किसी लाभार्थी की आधार संख्या का प्रमाणीकरण किसी भी बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण विधि (अर्थात् चेहरे की छवि, उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन आधारित प्रमाणीकरण) के माध्यम से किया जाता है और वह प्रमाणीकरण किसी भी कारण से विफल हो जाता है, जैसे कि बायोमेट्रिक सूचना की खराब गुणवत्ता, तो निम्नलिखित सुधारात्मक तंत्र अपनाए जाएंगे, अर्थात् :-

(क) यदि प्रमाणीकरण का कोई विशेष बायोमेट्रिक-आधारित तरीका सफल नहीं होता है, तो बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण का कोई अन्य तरीका, या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित प्रमाणीकरण जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, पेश किया जाएगा;

(ख) ऐसे मामलों में जहां बायोमेट्रिक-आधारित या ओटीपी-आधारित प्रमाणीकरण तरीके संभव नहीं हैं, वहां यथास्थिति आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से आधार संख्या की वास्तविकता स्थापित करने के पश्चात्, उक्त स्कीम योजना के अधीन लाभ निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर दिया जा सकेगा:

(i) आधार सुरक्षित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड जिसमें आधार कार्ड, आधार पत्र (अर्थात् आधार संख्या धारक को उसके आधार संख्या के सृजन पर जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (अर्थात् यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करने योग्य आधार पत्र की पासवर्ड से सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक प्रति या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है) सम्मिलित है, इसकी वास्तविकता आधार क्यूआर स्कैनर या एमआधार ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के पश्चात्।

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके एमआधार ऐप का उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है), इसकी वास्तविकता यूआईडीएआई की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए विवरण के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए संबंधित मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से दस्तावेज पर यूआईडीएआई के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से स्थापित होने के पश्चात्।

4. ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उक्त स्कीम के अधीन लाभ से किसी बच्चे को वंचित नहीं किया जाएगा-

(i) यदि वह प्रमाणीकरण पूरा करने पर अपनी पहचान स्थापित करने में या आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहने की स्थिति में है; या

(ii) यदि उसे आधार संख्या प्रदान नहीं की गई है और वह नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में है; और

(ख) उक्त स्कीम के अधीन लाभ ऐसे बच्चे को उसकी पहचान सत्यापित करके और उसके माता-पिता या विधिक संरक्षक के साथ उसके संबंध को स्थापित करके पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति से दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन लाभ दिया जाता है, तो उसके संबंध में एक अभिलेख रखा जाएगा, जिसकी विभाग द्वारा समय-समय पर समीक्षा और लेखापरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक लाभार्थी उक्त स्कीम के अधीन मिलने वाले लाभ से वंचित न रहें, मंत्रालय/विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-26011/04/2017-डीबीटी, तारीख 19 दिसंबर, 2017 (<https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध) में विनिर्दिष्ट अपवाद प्रचालन तंत्र का पालन करेगा।

6. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. SK-22011/13/2025-कौशल]

ऋचा शंकर, उपमहानिदेशक

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
(Department of Empowerment of Persons with Disabilities(Divyangjan))

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2025

S.O. 3036(E).—Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas the Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment in the Government of India (hereinafter referred to as the said Ministry or the said Department, as the case may be) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering the National Action Plan for Skill Development of Persons with Disabilities under the Central Sector Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disability Act, 2016 (SIPDA) (hereinafter referred to as the said scheme);

And whereas under the Scheme, cash benefits namely, transport cost, boarding and lodging cost, conveyance cost, cost for post placement support etc. (whichever is applicable as per norms of the Scheme (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Persons with Disabilities (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas the said Department is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.
- (2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment;

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Ministry or Department through its implementing agency shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Department for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

- (A) For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:
 - (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and
 - (b) Any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely:—
 - (i) Certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969, as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;
 - (ii) Indian passport;
 - (iii) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;

- (iv) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (v) In respect of a foreign national,—
- (V) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
- (VI) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
- (VII) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
- (VIII) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely:—
- (i) Ration card;
- (ii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (iii) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (iv) Indian passport;
- (vi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (vii) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (viii) In respect of a foreign national,—
- (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
- (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
- (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
- (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (ix) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (x) Any other document as the said Department may specify.
- (B) For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:
- (a) The acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the EID; and
- (b) Any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely:—
- (xi) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;
- (xii) Ration card;

- (xiii) Caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;
- (xiv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;
- (xv) Indian passport;
- (xvi) Certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised board of school education;
- (xvii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;
- (xviii) Disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (*Divyangjan*), Government of India;
- (xix) Driving licence issued in India;
- (xx) In respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by Child Care Institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, child welfare officer or probation officer of such institution; or
- (xxi) In respect of a foreign national,—
 - (I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;
 - (II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;
 - (III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;
 - (IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or
- (xxii) In respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890, the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or
- (xxiii) Any other document as the said Department may specify.

(4) An officer designated by the said Department in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3),—

- (a) the status of the enrolment request by submitting the Electronic Identification (EID) on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Electronic Identification (EID) is valid and that the enrolment request does not stand rejected; and
- (b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2. In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3. Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:—

- a. In case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

- b. In cases where biometric-based or OTP-based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following:
- (iii) An Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (*i.e.*, the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (*i.e.*, the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps.
 - (iv) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of UIDAI or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of UIDAI on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of UIDAI.
4. Notwithstanding anything contained hereinabove,—
- a. benefit under the said scheme shall not be denied to a child—
 - (i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or
 - (ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number; and
 - b. benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and
 - c. where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department.
5. In order to ensure that *bonafide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Ministry/Department through its implementing agency shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).
6. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. SK-22011/13/2025-Skill]

RICHA SHANKER, Dy. Director General